छोटी इकाइयों को दें भरपूर लोन

लखनऊ में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे की बैठक, एमएसएमई को ऋण के प्रवाह की समीक्षा भी की

लखनऊ। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने लखनऊ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को लेकर बैंकों, नाबार्ड, सिडबी, आईबीए, एमएसएमई संगठनों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और यूपी को दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाना एमएसएमई उद्यमियों की प्रगति के बिना संभव नहीं है। वह शनिवार को स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं बैठक में एमएसएमई को ऋण के प्रवाह की समीक्षा की कर रहे थे।

डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत और उत्तर प्रदेश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए छोटे उद्यमियों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। जीडीपी में 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। उन्होंने बैंकों से कहा कि एमएसएमई सेक्टर क्षमताओं को सीमित न करें, बल्कि उनको भरपूर लोन दें। संकट में पड़ी छोटी इकाइयों को दोबारा चलाने के लिए बैंकों को जोर देने के निर्देश दिए। महिला उद्यमियों को लेकर भी निर्देश दिए।

उन्होंने अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क और डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म पर बल दिया क्योंकि इनके जरिये लोन का प्रवाह तेज और जल्द होगा। एए आरबीआई की ऐसी इकाई है जो किसी व्यक्ति को सुरक्षित और डिजिटल रूप में एक वित्तीय संस्थान से प्राप्त अपने खाते की जानकारी अन्य वित्तीय संस्थान के साथ साझा करने में मदद करती है। बैठक में वित्तीय सेवा विभाग, प्रमुख बैंकों और नाबार्ड के वरिष्ठ प्रबंधन समेत एमएसएमई संघों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो